के आए हैं इसलिए भारत के पास उनके आंकड़े नहीं हैं।

(ग) भारतीय राजदूत ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय से सलाह मशविरा करके भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों को सहायता देने की योजनाएं बनाई हैं, यदि वे सामान्य तरीकों से न आ पा रहे हों तो, या उन्हें कोई खास कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो।

India's Sovereignty over Tin Bigha

6. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in terms of modalities of leasing Tin Bigha corridor to Bangla desh as finalised through exchange of letters between the Additional Secretary, Peoples' Republic of Bangladesh and the Foreign Secretary of the External Affairs Ministry, India, the right of passage for Bangladesh through Tin Bigha area, arms and army of Bangladesh have been ex cluded;

(b) if not, how it would affect India's sovereignty over Tin Bigha; and

(c) how far the clause 10 of the letter agreeing to, "provide mutual judicial assistance" is in conformity with India's judicial jurisdiction over an area under its sovereignly?

THE MINISTER OF STATE IN THE. MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALETRO): (a) No Sir, the right of passage for Bangladesh through the Tin Bigha Area does not exclude arms and army of Bangladesh, whose passage will be governed by Para 4 of the 1982 Tin Bigha Lease Agreement-

(b) It would not effect India's soverei gnty over the Tin Bigha as such access would toe subject to the agreed terms and modalities.

(c) Judicial jurisdiction of India and Bangladesh over Tin Bigha would be go verned by Para 9 of the 1982 Tin Bigha Lease Agreement. To ensure this, mutual judicial assistance will be given by India and Bangladesh to each other to the extent necessary.

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

7. [illegible]: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रेसलर संशोधन के बावजूद अमरीका पाकिस्तान को सैन्य तथा अन्य प्रकार की सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या रणनीति अपनाने का विचार रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फेलेरियो): (क) और (ख) अमरीकी सरकार का कहना यह है कि प्रेसलर संशोधन पाकिस्तान को सैनिक उपकरणों की "वाणिज्यक" बिक्री पर लागू नहीं होता है। अमरीकी सरकार के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1991 में इस प्रकार की बिक्री 22.781 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर थी।

(ग) सरकार इन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत के सुरक्षा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है और भारत की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती हैं।

Nuclear option far India

8. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether 'Nuclear option' is a dosed one or an open option for India;

(b) if it is 'closed one' what are the reasons therefor; and